जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 215 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 6 जून, 2026 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

प.बंगाल में भाजपा ने अपनी पूर्ण विजय को ''सील'' किया

कलकत्ता नगर निगम को भी टीएमसी के नियंत्रण से मुक्त कराया

- फिरहाद हाकिम ने मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया है और कमिश्नर नगर निगम को भंग करने जा रहे हैं।
- कलकत्ता के लोगों ने फिरहाद हाकिम के इस्तीफे पर खुशी जताई और उनकी कई शिकायतें कीं। बताया जाता है कि फिरहाद हाकिम ने एक बार कहा था कि हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि वे मुस्लिम परिवार में पैदा नहीं हुए हैं।
- पूर्ण बंगाल विजय का दूसरा चरण नई दिल्ली में चल रहा है। टीएमसी के कुल 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग गुट के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
- चर्चा है कि सांसद शुभेन्दु सेखर रॉय को इस गुट का नेता बनाया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि सेखर के पिता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ काम कर चुके हैं और प्र.मंत्री मोदी ने माल्दा में एक रैली में उनकी तारीफ भी की थी।
- अगर तृणमूल सांसद अलग गुट बना लेते हैं तो इससे भविष्य में महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में भाजपा को भारी मदद मिलेगी।

- अंजन रॉय -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 5 जून। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत तब हुआ था, जब मित्र देशों की सेनाएं 1945-46 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँचीं।

बंगाल में भाजपा की पूर्ण जीत पर उस समय मुहर लग गई जब उसने एक तरह से कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उस ऐतिहासिक कक्ष में अपना पद छोड़ा, जहां कभी सुभाष चंद्र बोस मेयर की प्रतिष्ठित कुर्सी पर बैठे थे।

''देशबंधु'' के नाम से प्रसिद्ध चितरंजन दास भी इसी मेयर की कुर्सी पर बैठे थे। एस्प्लनेड स्थित कलकत्ता कॉरपोरेशन का मुख्यालय, जिसे ''बड़ा लालबाड़ी,'' यानी ''राइटर्स बिल्डिंग'' की तुलना में ''छोटा लालबाड़ी'' कहा जाता है, अब भाजपा के हाथों में जा रहा है।

हकीम द्वारा मेयर पद से इस्तीफा देने के साथ ही नगर निगम ने निगम बोर्ड को भंग करने की तैयारी शुरू कर दी है। कलकत्ता कॉरपोरेशन के आयुक्त अब निगम बोर्ड को भंग कर प्रशासन अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं।

कट्टर कलकत्ता प्रेमी अब सामने आकर मेयर के कार्यकाल के दौरान उनके आचरण की तीखी आलोचना कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अपने प्रभावशाली दौर में फिरहाद हकीम ने कलकत्ता कॉरपोरेशन की परंपराओं का सम्मान नहीं किया।

उनके विरोधियों का आरोप है कि पद पर रहते हुए उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि बहुसंख्यक हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में नहीं हुआ। इस टिप्पणी से बहुसंख्यक समुदाय में व्यापक नाराजगी पैदा हुई थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साइबर अपराध मामलों में ईडी ने राजस्थान-पंजाब में छापे मारे

जयपुर। साइबर ठगी के जरिए अर्जित काली कमाई और फर्जी सिम कार्ड नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को राजस्थान और पंजाब में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने राजस्थान के जोधपुर, नागौर और किशनगढ़ सहित पंजाब के लुधियाना में कुल सात ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की।

ईडी सूत्रों के अनुसार कार्रवाई जोधपुर के बासनी स्थित साइबर क्राइम शाखा में दर्ज एक मामले के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि बड़ी संख्या में मोबाइल सिम कार्ड खरीदे जा रहे थे और बाद में उन्हें साइबर अपराधियों को बेचा जा रहा था। इन सिम कार्डों का उपयोग ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉलिंग और अन्य साइबर अपराधों में किया जा रहा था।

- जोधपुर में तीन, नागौर में दो तथा किशनगढ़ में एक स्थान पर छापों में अपराध से जुड़े दस्तावेजों, उपकरणों आदि की जाँच की गई।

जानकारी के अनुसार जोधपुर में तीन, नागौर में दो तथा किशनगढ़ और पंजाब के लुधियाना में एक-एक स्थान पर ईडी की टीमों ने दबिश दी।

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस नेटवर्क के तार विदेशों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

15 दिन पुराने सीजेपी मूवमैंट को नामचीन हस्तियों का समर्थन मिला

इनमें सोनम वांगचुक, एक्टर प्रकाश राज व शिव सेना के आदित्य ठाकरे आदि नाम शामिल हैं

- वांगचुक ने 6 जून के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा कर दी है और एक्टर प्रकाश राज भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं।
- इसके अलावा टीएमसी की महुआ मोईत्रा और कीर्ति आज़ाद ने भी सीजेपी को समर्थन दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि संविधान क्लब में सीजेपी की प्रैस कान्फ्रैंस के लिए आरजेडी के मनोज झा ने आर्थिक सहायता दी थी। हालांकि झा ने इससे इन्कार किया और कहा कि उन्होंने सिर्फ सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी।

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 जून। पंद्रह दिन पुराना ऑनलाइन आंदोलन, कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) कई प्रमुख समर्थकों को आकर्षित कर चुका है। इनमें जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, अभिनेता प्रकाश राज और शिव सेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे शामिल हैं।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके शनिवार को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं, और उनका इरादा शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का है। यह विरोध नीट-यूजी 2026 पेपर लीक के कारण 3 मई को परीक्षा रद्द होने और 21 जून को पुनः परीक्षा की घोषणा के बाद किया जा रहा है। ऐसी संभावना कम है कि केन्द्र सरकार दिपके और उनके तेजी से बढ़ते समर्थकों को शनिवार को प्रदर्शन की अनुमति देगी।

यूएस से उड़ान भरने से पहले दिपके ने समर्थकों से अपील की कि वे दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने न आएं। उन्होंने कहा कि वे संविधान पर भरोसा रख रहे हैं और संभावित गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले महीने सैटायरिकल डिजिटल आंदोलन के आधिकारिक एक्स अकाउंट को आईटी एक्ट की धारा 69 के तहत ब्लॉक कर दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह कदम इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर उठाया, जिसमें कहा गया कि यह अकाउंट राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करता है।

इस बीच, वांगचुक ने घोषणा की है कि अगर धर्मेन्द्र प्रधान उस तारीख तक इस्तीफा नहीं देते हैं, तो वे जंतर मंतर में सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि वे 6 जून से पहले दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस अभियान को ''सबसे प्रासंगिक कॉक्रोच आंदोलन'' बताया। शिव सेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी इसका समर्थन व्यक्त किया।

सीजेपी को समर्थन देने वाले अन्य प्रमुख व्यक्तियों में तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा और कीर्ति आज़ाद शामिल हैं। इसके अलावा, यह भी अटकलें हैं कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने बुधवार को संविधान क्लब में आयोजित सीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वित्तीय सहयोग दिया। लेकिन झा ने इसे नकारते हुए कहा कि उन्होंने केवल प्रेस मीट के लिए संविधान क्लब में जगह बुक कराने हेतु सिफारिश पत्र भेजा था।

क्या संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने की शर्त छोड़ दी है ट्रंप ने?

''पल में तोला पल में माशा'' कहावत को चरितार्थ करने वाले ट्रंप ने यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि संवर्धित यूरेनियम को ईरान से बाहर ले जाने का मुद्दा ''दफन'' हो चुका है

- अपने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना द्वारा संवर्धित यूरेनियम ईरान से बाहर जाने का विचार उन्हें पसंद नहीं है। ट्रंप की इस टिप्पणी ने सभी को हतप्रभ कर दिया, क्योंकि पूर्व में कई बार ट्रंप ने कहा था, अगर ईरान ने यूरेनियम नहीं ले जाने दिया तो वे उसका नामोनिशान मिटा देंगे।
- ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर दोनों देशों के बीच डील हो गई तो वे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा से मिलना चाहेंगे और यह उनके लिए सम्मान की बात होगी।

- डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली 5 जून। एक और हैरान करने वाले बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि वाशिंगटन को ईरान के साथ ऐसे शांति समझौते की जरूरत नहीं है, जिसमें इस्लामी गणराज्य के संवर्धित यूरेनियम (एनरिच्ड यूरेनियम) को देश से बाहर ले जाने की शर्त हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है, तो ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई से मिलना उनके लिए ''सम्मान की बात'' होगी। अपने हमेशा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने जल जीवन मिशन की सुनवाई एसीबी-2 को भेजी

जयपुर, 5 जून। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में अब एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 सुनवाई करेगी। एसीबी कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी की ओर से इस संबंध में हाईकोर्ट को पत्र लिखकर केस ट्रांसफर करने की गुहार की गई थी। इसके बाद, हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से मामले को लेकर एसीबी कोर्ट में लंबित मामलों को क्रम-2 कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया है, जहां अदालत मामले की सुनवाई 8 जून से करेगी। वहीं तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव और रिटायर आईएएस सुबोध अग्रवाल की जमानत अर्जी पर भी अब 8 जून को सुनवाई होगी।

- एसीबी कोर्ट-1 के पीठासीन अधिकारी ने हाई कोर्ट को पत्र लिखकर केस ट्रांसफर करने की प्रार्थना की थी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार बनाने के साथ ही मुश्किल शुरु हुई शिवकुमार की

शपथ लेने के दो दिन बाद ही एक वरिष्ठ मंत्री ने इस्तीफा दिया व कई अन्य ने विभाग के प्रति असंतोष जताया

- वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिला है, उन्होंने कहा कि वरिष्ठतम नेता होने के नाते उन्हें बेहतर विभाग मिलना चाहिए। रेड्डी ने कहा, उन्हें बेंगलुरु विकास विभाग देने का वादा किया गया था।
- एक अन्य मंत्री, के.एच. मुनिपप्पा, जो सात बार कोलार सीट से सांसद रहे हैं और वर्तमान में देवन हल्ली से विधायक हैं, ने विभाग के प्रति नाराज़गी जताई। एक अन्य विधायक के.जे. जॉर्ज अपने विभाग में किए जा रहे तबादलों से नाराज़ हैं।
- वहीं सतीश जारकीहोली को हालांकि उनका सार्वजनिक निर्माण विभाग पुनः मिल गया, पर, उनकी इच्छा प्रदेश अध्यक्ष बनने की भी है।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 5 जून। कर्नाटक के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो कई अन्य मंत्री बेहतर विभाग की मांग कर रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता उपेक्षा से नाराज़ हैं, मुस्लिम नेताओं ने मंत्रिमंडल में बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग उठाई है, और महिलाओं को प्रतिनिधित्व न मिलने पर भी आलोचना हो रही है। तीन दिन पुरानी डीके शिवकुमार सरकार आंतरिक राजनीतिक संकट में घिर गई है।

अब तक चार मंत्रियों ने हालात को लेकर अपनी नाराज़गी जताई है। पहला झटका शुक्रवार सुबह तब लगा, जब मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने यह कहते हुए इस्तीफा भेज दिया कि उन्हें आवंटित विभाग से वे असंतुष्ट हैं। इसके तुरंत बाद नई सरकार के दूसरे मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने भी अपने मंत्रालय को लेकर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद असंतोष का स्वर और तेज हो गया। मंत्री के.जे. जॉर्ज अपने विभाग में कथित ''हस्तक्षेप'' से नाराज़ बताए जा रहे हैं, जबकि सतीश जारकीहोली ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी महत्वाकांक्षा केवल मंत्री पद तक सीमित नहीं थी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पाने वाले मुनियप्पा ने कहा कि पार्टी के ''सबसे वरिष्ठ'' नेताओं में से एक होने के नाते, वे इससे बेहतर विभाग के हकदार थे।

उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपनी अपेक्षाओं के बारे में राहुल गांधी सहित, पार्टी नेतृत्व को पहले ही अवगत करा दिया था।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वे दिए गए विभाग से नाराज़ हैं, तो मुनियप्पा ने कहा कि उन्हें ऐसा ''महत्वपूर्ण विभाग'' दिया जाना चाहिए जहाँ वे जनता के लिए बेहतर ढंग से काम कर सकें।

के.एच. मुनियप्पा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कोलार लोकसभा सीट से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खड़गे ने राज्यसभा का नामांकन भरा

बेंगलुरु, 05 जून (हि.स.)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।

- राहुल गांधी, वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया, सुरजेवाला आदि नामांकन के समय मौजूद थे।

राज्यसभा चुनाव 18 जून को होना है। नामांकन दाखिल करने के दौरान, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, रणदीप सिंह सुरजेवाला तथा कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद सहित, अनेक प्रमुख नेता उपस्थित थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकारी बॉण्ड में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को वित्त मंत्रालय ने दी भारी टैक्स छूट

ईरान युद्ध, महंगा तेल, रूपये की गिरती कीमत और तीन दिन में विदेशी निवेशकों द्वारा 34,000 करोड़ रुपये निकाला जाना है इस फैसले की बुनियाद

- उल्लेखनीय है इस वर्ष अब तक स्थानीय शेयर बाजार से 2.6 लाख करोड़ रुपये की निकासी हुई है, जो 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।
- वहीं ईरान युद्ध और उससे जुड़े आर्थिक संकटों के कारण रुपया 20 मई, 2026 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96.86 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

-कार्यालय संवाददाता-

नई दिल्ली, 5 जून। वैश्विक पूंजी को आकर्षित करते हुए, सरकार ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेश संस्थानों (एफपीआई) द्वारा किए गए निवेशों पर लागू कर व्यवस्था को युक्ति संगत बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत, ऐसे निवेशों को ब्याज या पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट दी जाएगी। इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान व्यवस्था कई तुलनीय देशों के अनुरूप हो जाएगी।

यह छूट 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसका अर्थ है कि जी-सेक (गवरमैंट सैक्टर बॉण्ड) में निवेश से जुड़े मामलों में एफपीआई को 01 अप्रैल 2026 या उसके बाद प्राप्त होने वाले किसी भी तरह के ब्याज या पूंजीगत लाभ पर यह छूट लागू होगी।

सरकार ने दीर्घकालिक एवं स्थिर पूंजी आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर हटाने का फैसला किया है, क्योंकि इन माध्यमों की अवधि लंबी होती है। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष अब तक स्थानीय शेयर बाजार से 2.6 लाख करोड़ रुपये निकाले हैं, जो 2025 में निकाले गए 1.66 लाख करोड़ रुपये से कहीं अधिक है। इसकी वजह वैश्विक अनिश्चितता रही है। केवल जून के पहले तीन दिन में ही विदेशी निवेशकों ने शेयरों से करीब 34,000 करोड़ रुपये निकाले, जिससे रुपये पर अतिरिक्त दबाव पड़ा।

सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ती के अनुसार इन प्रयासों का उद्देश्य भारतीय इक्विटी बाजार और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों का दायरा बढ़ाना है, साथ ही दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक में निवेश करने के इच्छुक वैश्विक निवेशकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। इससे टिकाऊ और निरंतर विदेशी पूंजी का प्रवाह सुनिश्चित होगा, जो दीर्घकालिक निवेशकों जैसे पेंशन फंड, बीमा कंपनियों और संप्रभु धन कोष (एसडब्ल्यूएफ) के रूप में स्थिर और व्यवस्थित तरीके से आएगा।

वित्त मंत्रालय के अनुसार इन उपायों से एक सुचारू उपज वक्र के विकास में मदद मिलेगी और पेंशन फंड, बीमा कंपनियां और संप्रभु धन कोष जैसे दीर्घकालिक निवेशकों सहित दीर्घकालिक, विदेशी पूंजी का स्थिर व्यवस्थित प्रवाह आकर्षित होगा। इससे देश में विदेशी मुद्रा प्रवाह को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

वित्त मंत्रालय का कहना है कि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें 15, 30 और 40 वर्षों की अवधि के सरकारी प्रतिभूतियों के नए निर्गमों के साथ-साथ एफएआर-पात्र प्रतिभूतियों की अवधि के संप्रभु हरित बॉंड (एसजीआरबी) को भी शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सामान्य मार्ग के अंतर्गत एफपीआई निवेशों के संबंध में, विदेशी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चर्चित शिक्षक खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

पटना, 05 जून। राजधानी पटना में चर्चित शिक्षक और कोचिंग संचालक खान सर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कदमकुआं थाना में उनके खिलाफ हत्या की कोशिश और शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्ट) से संबंधित

- कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश तथा आर्म्स एक्ट में भी धाराओं में मामला दर्ज हुआ।

धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा दर्ज मामले के बाद पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है और जांच एजेंसियां मामले की विस्तृत पड़ताल में जुट गई हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह मामला खान सर के सुरक्षा गार्डों के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)